P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika
E: ISSN NO.: 2349-980X Vol-II * Issue-X*June-2015

वैश्वीकरण एवं विकासशील भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवर्तन एक अध्ययन

बी. डी. खरबार
सहायक प्राध्यापक,
भूगोल विभाग,
शासकीय महाविधालय सिलवानी,
रायसेन

सारांश

वैश्वीकरण

वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का समन्वय किया जाता है ताकि वस्तुओं एवं सेवाओं, प्रौद्योगिकी पूँजी तथा श्रम अथवा मानवीय पूँजी का विभिन्न देशों के बीच निर्वाध प्रवाह हो सके। इसके चार प्रमुख अंग है :–

1. व्यापार अवरोधकों को कम करना ताकि वस्तुओं एवं सेवाओं का बरोक–टोक आदान–प्रदान हो सके।
2. ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करना ताकि विभिन्न देशों के बीच पूँजी का स्वतंत्र प्रवाह हो सके।
3. ऐसा वातावरण बनाना ताकि प्रौद्योगिकी का निर्बाध प्रवाह हो सके।
4. ऐसा वातावरण तैयार करना जिससे विश्व के विभिन्न देशों के बीच श्रम का निर्बाध प्रवाह हो सके।

वैश्वीकरण के सर्मथक विशेषकर विकसित देश वैश्वीकरण की परिभाषा को पहले तीन अंगो तक ही सीमित करने पर बल देते है। अर्थात निर्बाध व्यापार प्रवाह, निर्बाध पूँजी प्रवाह और निर्बाध प्रौद्योगिकी प्रवाह। किन्तु विकासशील देशों के अर्थशास्त्री यह मत रखते है कि यदि संसार को सार्वभौम ग्राम (Global Village) के रुप में कल्पित करना है तो श्रम के निर्बाध प्रवाह की उर्पेक्षा नही की जा सकतो है।

मुख्य शब्द : वैश्वीकरण, भूमण्डलीकरण, अर्थव्यवस्था।

प्रस्तावना

भूमण्डलीकरण जो एक रोमांचक शब्द है जो यह स्पष्ट करता है कि विभिन्न राष्ट्र–राज्यों का विश्व व्यापार संगठन के ढांचे के अधीन एकीकृत कर देना चाहिए, किन्तु थोड़ा गहन विचार करने से यह बात स्पष्ट होती है यह तुलनात्मक लागत–लाभ (Comparative Cost) के सिद्धान्त का आधुनिक विवरण है जिसे प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने प्रतिपादित किया था ताकि ग्रेट ब्रिटेन का कम विकसित देशों में, जो उस समय उपनिवेश ही थे, बेरोक–टोक वस्तुओं के निर्यात–आयात के लिए सैद्धान्तिक आधार मिल सके। यह तर्क दिया गया कि अन्तराष्ट्रीय विशिष्टीकरण से ऐसे देशों को लाभ होगा जो व्यापार सम्बंध कायम करते है। अब यही तर्क भूमण्डलीकरण के सर्मथक पेश कर रहे है। वे विकास के लिए आयात–प्रतिस्थापन व्यापार नीति की अपेक्षा निर्यात प्रेरित विकास नीति पर बल दे रहे है। 18वी, 19वी एवं 20वी शताब्दी के पूर्वार्द्ध में साम्राज्यवादी देशों ने भी उपनिवेश देशों में पूँजी एवं प्रौधोगिकी के प्रवाह को बढ़ावा देन पर बल दिया, किन्तु वे उस समय शासक होने के कारण इन राज्यों को इस नीति को स्वीकार करने के लिए मजबूर कर सकते थे, किन्तु इस सम्बध में उपलब्ध ऐतिहासिक प्रमाणों से पता चलता है कि इन व्यापार पूँजी एवं प्रौधागिकी के प्रवाहों द्वारा साम्राज्यवादी देश उपनिवेशिक देशों में उनके संसाधनों का शोषण करने में सफल हुए। इस प्रकार साम्राज्यवादी देश उपनिवेशक देशों के शोषण के माध्यम से समृद्ध बनते गए जबकि उपनिवेश आर्थिक गतिरोध और गरीबी के चुगंल में फंसे रहे।

पिछले दो दशकों के दौरान विकसित राष्ट्रों विशेषकर यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमरीका ने भूमण्डलीकरण को एक नये मंत्र के रुप में विश्व विकास के लिए अपनाने पर बल दिया है भूमण्डलीकरण के समर्थक यह आशा करते है कि हम विकासशील राष्ट्र यह मानते है कि वे अब ईमानदारी से यह कह रहे है कि भ्मण्डलीकरण की नीतियो के परिणामस्वरुप विकासशील दुनिया की स्पर्द्धा शक्ति उन्नत होगी और वे तीव्र विकास युग का प्रारम्भ कर सकेगें। अर्थात विकासशील देशों को फुसलाया जाता है और अनेक प्रकार के नरम और सख्त दबावों के प्रभाव से उन्हें स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जाता है।

इसी के परिणामस्वरुप भारत में 1991 में व्यापार अवरोधकों को समाप्त प्रक्रिया 1991 में आरम्भ की गई और प्रत्येक वर्ष भारत सरकार सीमा शुल्कों में कटौती मात्रात्मक प्रतिबंधों को हटाने की घोषणा करती रही है। यह तक दिया जाता है कि इससे वस्तुओं, पूँजी एवं प्रौधागिकी का निर्बाध प्रवाह होने लगेगा, फलतः भूमण्डलीकरण विकासशील देशों के लिए प्रेरणा शक्ति बन सकती है जिससे इन देशों का तीव्र गति से विकास होने लगेगा। भारत जैसे विकासशील देश के लिए इससे नए बाजार एवं नई प्रौधोगिकी के लिए पहुँच खुल जावेगें। अर्थात आयात–प्रतिस्थापन रणनीति की अपेक्षा पिछले दो दषको के दौरान निर्यात–प्रेरित रणनीति अपनाई गई है। सूचना एवं संचार प्रौधोगिकी में हुई प्रगति ने भी भूमण्डलीकरण की प्रक्रिया को बढ़ा दिया है।

भारत ने पिछले दो दशक से ऊपर भूमण्डलीकरण की नीति का अनुसरण किया है अतः इन नीतियो के अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा करने की आवश्यकता है।

वैश्वीकरण की विशेषताएं

1. वैश्वीकरण के अन्तर्गत दश की अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत किया जाता है।,
2. वस्तुओं एवे सेवाओं का एक देश स दूसरे देश में निर्बाध प्रवाह होता है।
3. बहुराष्टोय कम्पनियों का विस्तार होता है।
4. सरकार की राष्टोय समष्ट्रि आर्थिक नीतियो का क्षेत्र कम हो जाता है।

वैश्वीकरण से लाभ

1. वैश्वीकरण से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रोत्साहित होगा जिसके फलस्वरुप विकासशील दश बिना अंतराष्ट्रीय ऋणग्रस्तता, कायम किए अपने विकास के लिए पूँजी प्राप्त कर सकेगें।
2. वैश्वीकरण से विकासशील देशों को उन्नत देशों द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी स्वतः प्राप्त हो जावेगी।
3. वैश्वीकरण से ज्ञान का तेजी से विस्तार होता है जिसके फलस्वरुप विकासशील देश अपने उत्पादन एवं उत्पादकता के स्तर को उन्नत कर सकते है इस तरह यह उत्पादकता के अंतराष्टोय स्तर को प्राप्त करने में सहायक है।
4. वैश्वीकरण विकासशील देशों को विकसित देशो में अपनी उपज का निर्यात करने की पहुँच का विस्तार करता है, साथ ही यह विकासशील देशो को उच्च गुणवत्ता वाली उपभोग वस्तुओं विशेषकर चिरकालीन उपभोग वस्तुओं को अपेक्षाकृत कम कीमत पर प्राप्त करने योग्य बनता है।
5. वैश्वीकरण से परिवहन एवं संचार की लागत कम हो जाती है। इससे प्रशुल्क भी कम हो जाते ह तथा सकल घरेलु उत्पाद के प्रतिशत के रुप में विदेशी व्यापार का भाग बढ़ जाता है।

वैश्वीकरण को विकास के लिए प्रौद्योगिकीय प्रगति तथा उत्पादकता में वृद्धि का इंजन कहा जा सकता है यह रोजगार के विस्तार के साथ गरीबी कम करने तथा आधुनिकरण का कारण बन जाता है।

भारत में वैश्वीकरण

भारतीय संदर्भ में वैश्वीकरण का तात्पर्य–भारतीय अर्थव्यवस्था में विदेशी कम्पनियों एवं निगमों के आने के लिए मार्ग प्रशस्त करना, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को अनुमति देना तथा इनके मार्ग में आने वाली बाधाओं, प्रतिबधों एवं अवरोधों को हटाना, भारतीय कम्पनिया को विदेशी कम्पनियो के साथ मिलकर संयुक्त उद्यम स्थापित करने की अनुमति देना, व्यापार में मात्रात्मक एवं गैर मात्रात्मक प्रतिबंधों को समाप्त करना, निजीकरण एवं उदारीकरण को बढ़ावा देना आदि, इस तरह भूमण्डलीकरण का अथ है भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ना है ताकि वह विश्व के देशों से प्रतियोगिता करते हुए तेजी से विकास कर सके।

भारत में वैश्वीकरण के घटक

भारत में वैश्वीकरण को प्ररित करने वाले प्रमुख घटक निम्नवत है–

उन्नत प्रौद्योगिकी

वैश्वीकरण को प्रोत्साहित करने में उन्नत प्रौधोगिकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कम लागत पर सख्ती और गुणवत्तायुक्त वस्तुओं का उत्पादन उन्नत प्रौधांगिकी से ही संभव है।

उदारवादी नीतियाँ

विभिन्न देशो द्वारा अपनायी जाने वाली उदारवादी नीतियों से ही वैश्वीकरण का मार्ग प्रशस्त हो सका है।

प्रतिस्पर्द्धा

प्रतिस्पर्द्धा पूँजीवादी अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता है। प्रतिस्पर्द्धा के कारण ही कम्पनियों को विदेशो में नए बाजार खोजने की आवश्यकता हुई तथा इसी के फलस्वरुप उत्पादन एवं विक्रय की नवीन विधियों का विकास हुआ। विदेशी कम्पनियो की प्रतिस्पर्द्धा के डर से ही घरेलू कम्पनियों विश्व बाजार में अपना ध्यान लगाने को बाध्य हुई और वैश्वीकरण को बढ़ावा मिला।

विकासशील देशों के अनुभव

वैश्वीकरण की प्रक्रिया को अपनाने वाली विकासशील अर्थव्यवस्था वाले देश चीन, कोरिया, थाईलैण्ड, हांगकांग, सिंगापुर आदि आर्थिक विकास की ऊँची दर प्राप्त करने में सफल रहे है। वैश्वोकरण के इस सफल अनुभव ने भी भारत को अपनी अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण करने के लिये प्रेरित किया है।

अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक का दबाव

भारत की उदारीकरण एवं वैश्वीकरण की प्रक्रिया को अपनाने के लिए विश्व बैंक तथा अंतराष्टोय मुद्रा कोष भी भारत पर दबाव डाल रहे है।

पूँजी बाजार का सार्वभौमीकरण होना

भारत में वैश्वीकरण के प्रयास

भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण की प्रक्रिया वर्ष 1991 में घोषित नवीन आर्थिक नीति को अपनाने के साथ ही प्रारम्भ हो गई जिसमें भारत सरकार ने वैश्वीकरण के परिपक्ष्य में प्रयास किये गये है।

1. **रूपये को पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया**– वैश्वीकरण को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रुपये को वर्ष 1994 में चालू खते पर पूर्ण परिवर्तनीय बनाया

गया है चालू खाते से सभी लेन देन के लिए विदेशो विनिमय को खरीदने एवं बेचने की स्वतंत्रता दी गई है।

2. **आयात उदारीकरण**– वैश्वीकरण के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए देश में आयात को उदार बनाया गया है आयातों पर सभी मात्रात्मक प्रतिबंध 1 अपल 2001 से हटा लिए गए है आयात शुल्कों में भी भारी कमी की गई है। कुछ वस्तुओं पर कस्टम ड्यूटी 150 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत के न्यून स्तर पर लाया गया है।
3. **देश में विदेशी पूंजी के लिए अर्थव्यवस्था को खोल दिया गया**– भारत सरकार द्वारा देश में विदेशी पूॅजी को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रयास किए गये जा रहे है विदेशी निवेशकों तथा अनिवासी भारतीयो के लिये विभिन्न प्रकार की सुविधाए एवं प्रेरणाएं नई आर्थिक नीति में प्रदान की गई है। विदेशी प्रत्यक्ष निर्देश के लिए अर्थव्यवस्था में दरवाजे खोल दिए गये है। विभिन्न उधोगो में 26,49 प्रतिशत 51 प्रतिशत तथा 74 प्रतिशत तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश आमंत्रित किए गये है प्रमुख उधाग डग्स एवं फार्मास्युटिकल्स, होटल, पर्यटन विधुत्त उत्पादन, ऑयल रिफाइनरी, सड़क निर्माण, पोर्ट आदि। बीमा क्षेत्र को भी आंशिक रुप से खोल दिया गया है।
4. विदशो कम्पनियों को अनुमति दी गई है कि वे अपने टेडमार्क का प्रयोग भारत में भी कर सकते है तथा उन व्यापारिक क्रियाओं में भाग ले सकती है जो औद्योगिक प्रकृति की है। विदेशी कम्पनियॉ भारतीय रिजर्व बैक की अनुमति के बिना जमाओं को स्वीकार कर सकती है तथा उधार भी ले सकती है और स्थिर सम्पति भी क्रय कर सकती है।

वैश्वीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

भारत म अब तक दो दशक से ऊपर भूमण्डलीकरण की नीति का अनुसरण किया है इन नीतियों का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव सकारात्मक एवं नकारात्मक रुप में देखने की आवश्यकता है

सकारात्मक प्रभाव

1. भारत का वस्तुओ एवं सेवाआ के विश्व निर्यात में योगदान
2. भारत में विदेशी निवेश का प्रवाह
3. स्वीकृत विदेशी निवेश और वास्तविक अन्तः प्रवाह पर प्रभाव
4. जीवन स्तर में सुधार
5. भारतीय उद्योगो पर प्रभाव

नकारात्मक प्रभाव

1. निर्यात की तुलना में आयात में वृद्धि
2. सकल देशीय उत्पाद में उच्च वृद्धि दर के साथ रोजगार में गिरावट
3. भूमण्डलीकरण उपरान्त काल में गरीबी कम करने पर प्रभाव भारत कृषि प्रधान देश है अतः वैश्वीकरण को अंगीकृत करते समय भारतीय कृषि एवं उससे जुड़े उद्योगो और भारतीय किसान की परिस्थितियॉ का ध्यान रखा जाना आवश्यक होगा।

संदर्भ सूची

1. भूगोल, डॉ. चर्तुभुज मामोरिया, डॉ. बी. एल. शर्मा, साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा 2010
2. www.indian business.nic.in
3. www.indian Economy